B-2

L-28

MIH

शाही नौसेना विद्रोह - 1946

• 1946 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोहों की शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ गई जब भारतीय नौ सैनिकों ने विद्रोह किया। इस शाही नौसेना की पृष्ठभूमि निम्नलिखित तत्वों ने तैयार की-

(i) भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार से निरंतर असंतुष्ठ बने रहे क्योंकि उन्हें नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ता था और ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के चरित्र के बारे में अपमान-जनक टिप्पणी करते रहते थे साथ ही नौसैनिकों को दिया जाने वाल अखाद्य भोजन भी उनको विद्रोही बना रहा था।

(ii) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से बाहरी मोर्चे पर लड़ने गए तो अन्य देशों के सैनिकों के साथ सम्पर्क होने से इनमें अपने देश की आजादी के प्रति भी राष्ट्रवादी भावना मजबूत होने लगी। जिसे भारत छोड़ो आन्दोलन की लोकप्रियता ने और बढ़ावा दिया।

(iii) आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों तथा बाद में लाल किला केस के कारण भी इन नौसैनिकों की आस्था ब्रिटिश सत्ता से हटने लगी थी और इन्हीं परिस्थितियों में जब भारतीय नौसेना के तलवार (बम्बे) नामक जहाज पर एक सैनिक ने भारत छोड़ो का नारा लिखा, तो उसकी गिरफ्तारी से नाराज होकर असंतुष्ट नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया।

प्रभात:- बम्बई "भारतीय नौसैनिक जहाज तलवार" नामक जहाज से आरम्भ होकर यह विद्रोह शीघ्र ही कलकत्ता करांची, मद्रास जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी प्रसारित हो गया और इस नौसैनिक विद्रोह ने इतना प्रभावी रूप ले लिया कि ब्रिटिश सरकार को युद्ध की धमकी देनी पड़ी।

इस विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया कि अब नागरिक और सैनिक लक्ष्य एक हो गए हैं और वह है "भारत की आजादी"। इस विद्रोह की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी कि लोग अपने सांप्रदायिक मतभेदों को भुलाकर इन सैनिकों के समर्थन में सड़क पर उतर आए और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हमारा राष्ट्रीय संघर्ष पुनः ऊर्जावान हो गया।

शाही नौसेना विद्रोह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि- अब बिना किसी संगठन, बिना किसी लोकप्रिय नेतृत्व के भी प्रभावी विद्रोह किया जा सकता है। इस तरह अब स्वतः स्फूर्त विद्रोह हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की पहचान बन गए।

उल्लेखनीय है कि जब ऐसे स्वतः स्फूर्त विद्रोह प्रत्येक क्षेत्र में आरम्भ हो जाएं तो किसी भी सत्ता का बने रहना असम्भव हो जाता है इस तरह शाही नौसैनिक विद्रोह ने भारत की आजादी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही भूमिका निभाई। कहा जा सकता है कि यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

यद्यपि हमें यह भी स्वीकारना होगा कि इस महान विद्रोह व उसके प्रभाव को भारतीय इतिहास लेखन उतना महत्व नहीं दे सका जितना की अपेक्षित था।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

देशी रियासतें

Key Point, (महत्वपूर्ण बिन्दु):-

• ब्रिटिश शासन के दौरान भारत मुख्यत: ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के अन्तर्गत शासित हो रहा था जहाँ अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया वह ब्रिटिश भारत कहलाया और जहाँ देशी शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन बना रहा उन्हे देशी रियासतें कहा गया।

ये रियासतें भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% और कुल जनसंख्या का लगभग 28 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती थी। उल्लेखनीय है कि इन रियासतों में विभिन्न प्रकार की विषमताएँ उपस्थित थी न केवल क्षेत्रफल व जनसंख्या अपितु सम्पन्नता के आधार पर भी इनमें अत्यधिक अन्तर स्थापित था उदाहरण स्वरूप- भोपाल व बिलबारी रियासत की तुलना।

प्रश्न- अधीनस्थ पार्थक्य की नीति से आप क्या समझते हैं और अंग्रेजों ने इसका रूपान्तरण अधीनस्थ सम्मेलन की नीति मे क्यों किया?

उत्तर- • ब्रिटिश सत्ता व देशी रियासतों के बीच संबंध समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं

• इस परिप्रेक्ष्य में 1813 से 1858 का दौर अधीनस्थ पार्थक्य संबंध कहलाया। वस्तुत: 1813 से 1857 के बीच अंग्रेजों ने तात्कालिक भारत की बड़ी

शक्तियों को पराहत कर दिया था अतः उनमें सर्वोच्चता की भावना का पैदा होना आवश्यक था। और अब वे घेरे की नीति व सहायक सन्धि से आगे बढ़कर देशी रियासतों को अपनी सर्वोच्चता स्वीकार कराते हुए उन्हें अपना अधीनस्थ बनालिया।

दूसरी तरफ देशी रियासतें भी इस स्थिति में नहीं थी कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर सकें। और साथ ही राजाओं और नवाबों को अधीनता स्वीकार करने में अपने स्वार्थों की पूर्ति सहज लगने लगी।

किन्तु इन रियासतों को मिलकर विद्रोह करने की संभावना को देखते हुए अंग्रेजों ने रियासतों के विलय या सम्मेलन पर रोक लगा दी और इसी सन्दर्भ में यह अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहलायी।

1857 के महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रियासतों के साथ अपने संबंधों की पुनर्समीक्षा की और उदारवादी रूप देते हुए अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को अधीनस्थ सम्मेलन में रूपान्तरित कर दिया जिसके मुख्य कारण थे-

- 1857 के महाविद्रोह में रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता का साथ दिया था अर्थात ये रियासतें इस पक्ष में थीं कि ब्रिटिश सत्ता यहाँ बनी रहे अतः इन्हें पुरस्कृत करने के

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

दृष्टिकोण से यह रूपान्तरण किया गया।

- अंग्रेजों को अब इस बात का भय ज्यादा रहा था कि अब रियासतें मिलकर विद्रोह करेंगी।
- 1860 के बाद अंग्रेजों ने वित्तीय पूँजीवाद को अपनाया जिसके तहत रेलवे व सड़क जैसी अवसंरचनाओं में निवेश किया जाने लगा अतः रियासतों का अलगाव मिटाना आवश्यक हो गया क्योंकि अब सम्पूर्ण भारत में यातायात, परिवहन व संचार व्यवस्था को जोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया था।

विशेष :-

- 1921 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत एक परामर्शदात्री/सलाहकारी निकाय के रूप में "नरेन्द्र मण्डल" का गठन किया गया जो ब्रिटिश सत्ता के साथ देशी रियासतों के सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने का प्रमाण था प्रतिवर्ष इनका प्रतिनिधि मण्डल अपने सुझावों को लेकर ब्रिटिश सत्ता के साथ विमर्श करने का अधिकारी बना दिया गया
- 1924 में साइमन कमीशन के साथ ही ब्रिटिश सत्ता ने रियासतों के साथ संबंधों की पुनर्व्याख्या के लिए "बटलर कमीशन" का गठन किया। उल्लेखनीय है कि

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Your Trusted Learning Platform
KHAN SIR

इस समय ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव से रियासतों की जनता भी प्रेरित होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रजामण्डल आंदोलन का समर्थन करने लगी थी अतः रियासतों और ब्रिटिश सत्ता दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई इसीलिए बटलर कमीशन का गठन किया गया जिसमें तीन अनुशंसाएँ थीं।

(i) सर्वोच्चता, सर्वोच्चता ही रहनी चाहिए।

(ii) ब्रिटिश सत्ता को कोई भी प्रस्ताव या नियम बनाते समय रियासतों के रीत रिवाजों व परम्पराओं का ध्यान रखना चाहिए तथा इनसे संवाद के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) बिना शासकों की सहमती के किसी भी रियासत को किसी अन्य सत्ता को नहीं सौंपना चाहिए।

बटलर कमीशन के ये प्रस्ताव अस्पष्ट बने रहे और रियासती जनता ने इन्हें अपनी माँगों के विरुद्ध माना अतः ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का नेतृत्व बटलर कमीशन के प्रस्तावों से संतुष्ट न हो सका।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

प्रजामण्डल आंन्दोलन व कांग्रेस :-

देशी रियासतों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को लेकर विशेषतः 1920 के दशक में प्रजामण्डल आंन्दोलन आरम्भ होने लगे। उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में ये आंदोलन देशी शासकों के विरुद्ध थे, किन्तु बाद में अपनी समस्या की मूल जड़ को समझते हुए इन्होनें ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आवाज उठायी।

विभिन्न रियासतों में स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस का गठन कर सांगठनिक तरीके से जनता के हितों की मांग की जाने लगी और 1927 में बम्बई में बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी आदि के नेतृत्व में ऑल इण्डिया स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस का गठन किया गया तो अब विभिन्न रियासतों की मांगों ने समूहिकता का रूप ग्रहण कर लिया और अब रियासतों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना एक लोकप्रिय विषय बन गया

1920 के दशक में कांग्रेस प्रजामण्डल आन्दोलन के प्रति "सतर्कता की नीति" अपनाती रही और गांधी ने कांग्रेस के नाम से रियासतों में आन्दोलन का समर्थन नही किया क्योंकि वे अभी राष्ट्रीय संघर्ष में दोहरी

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

चुनौती खड़ा करना नहीं चाहते थे यद्यपि कांग्रेस के कई नेताओं का प्रजामण्डल आन्दोलन के प्रति रूख सकारात्मक रहा।

1939 के लुधियाना अधिवेशन में ऑल इण्डिया स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस की अध्यक्षता जब नेहरू ने की तो यह संकेत था कि अब कांग्रेस व प्रजामण्डल के लक्ष्य एक होने लगे हैं 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव में गाँधी ने रियासतों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की माँग कर अब राष्ट्रीय संघर्ष को रियासतों से एकीकृत कर दिया।

देशी रियासतों का एकीकरण :-

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष प्रबल चुनौती यह उभरी की 565 रियासतों का एकीकरण भारत में कैसे किया जाए, उन्हें आधुनिक प्रशासनिक इकाई का रूप कैसे दिया जाए? स्मरणीय है कि भारत अनेक विषम रियासतों विभिन्न संप्रदायों व विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है अतः यह विषय और भी जटिल हो गया।

1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से इन रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई और उन्हें यह विकल्प दिया गया कि

भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुने या फिर अपने आप को स्वायत्त घोषित कर दें।

इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए रियासतों का एकीकरण विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया, जिन्होंने सलाहकार वी. पी. मेनन के साथ इस चुनौती का समाधान ढूँढ निकाला।

वस्तुतः भारत संघ के निर्माण में मुख्यतः तीन समस्याएँ उभरीं-

(i) 15 Aug 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर के अतिरिक्त अन्य रियासतों ने भारतीय संघ में विलय की सहमति दे दी। अर्थात पहली चुनौती इन तीनों रियासतों में भारत के विलय की थी।

(ii) राजाओं और नवाबों को यह भय सता रहा था कि संघ में शामिल होने के बाद उनकी संपत्ति, प्रतिष्ठा व अधिकारों में कमी आ जाएगी, और उन्हें यह भय अधिक सताने लगा कि कांग्रेस सामाजवादी विचारों को स्वीकारती दिखने लगी थी।

(iii) विभिन्न विषम रियासतों को संघीय ढाँचे में आधुनिक प्रशासनिक इकाई के रूप में कैसे ढाला जाए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR